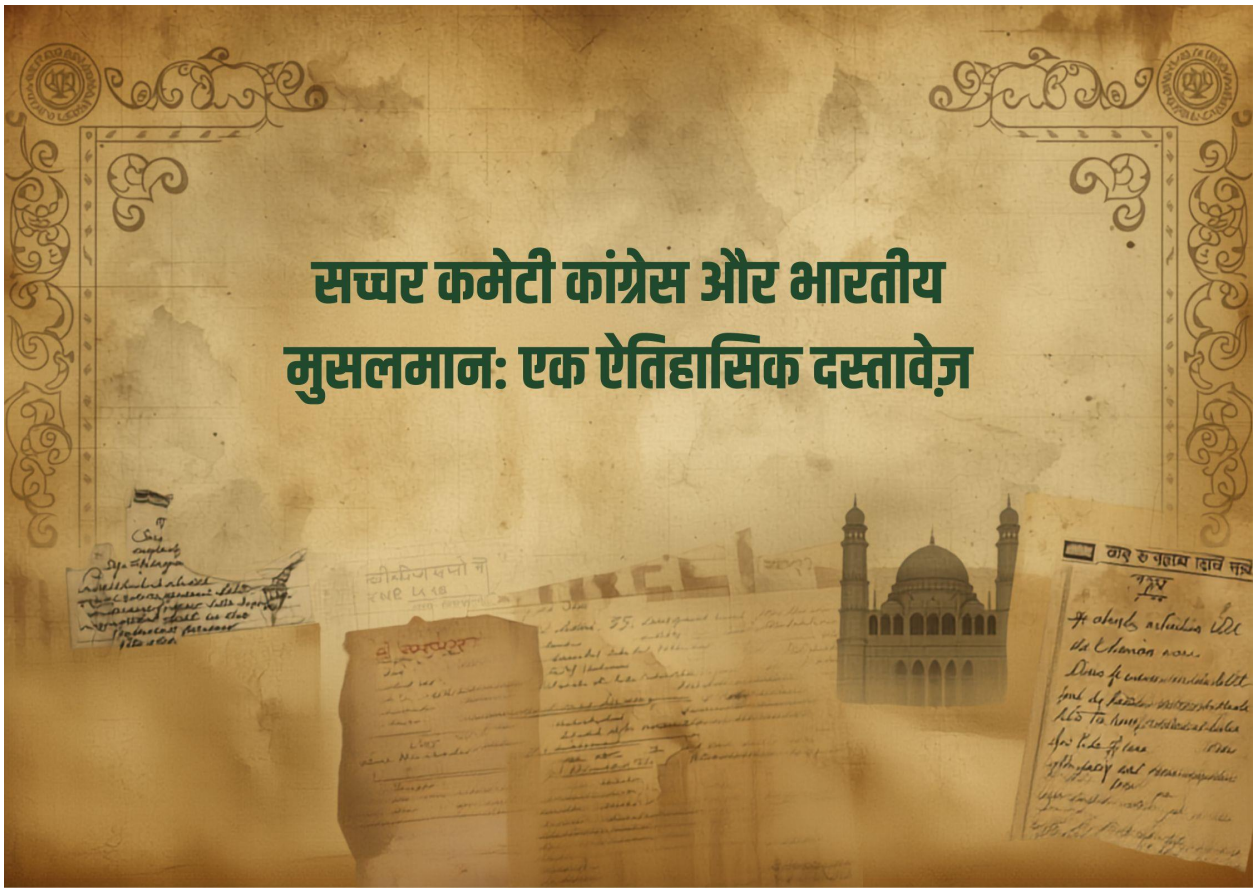

सच्चर कमेटी, कांग्रेस और भारतीय मुसलमान: एक ऐतिहासिक दस्तावेज़

विचारक : डॉ सैयद नासिर शाह

भारत के मुसलमानों की माशी (आर्थिक), समाजी (सामाजिक), और तालीमी (शैक्षणिक) हालत को समझने के लिए 'सच्चर कमेटी रिपोर्ट' एक आईने की तरह है। 2005 में यूपीए (कांग्रेस)

सरकार ने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हिदायत पर जस्टिस राजिंदर सच्चर की क़यादत में एक 7-रुकनी (7-सदस्यीय) कमेटी बनाई थी। इसका मक़सद मुसलमानों की ज़मीनी हक़ीक़त का पता लगाना था।

जब नवंबर 2006 में यह रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आई, तो इसने पूरे देश को हैरान कर दिया। हालांकि यह रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने बनवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े (statistics) दरअसल 1947 से लेकर 2006 तक–जिसमें सबसे ज़्यादा अरसा कांग्रेस ने हुकूमत की–मु मुसलमानों के साथ हुए सियासी और माशी नुक़सान का सबसे बड़ा सुबूत बन गए। इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी के 60 साल बाद मुसलमानों की हालत कई मामलों में दलित (SC/ST) तबक़े से भी बदतर हो चुकी थी।

नीचे सच्चर कमेटी रिपोर्ट के अहम आंकड़ों (data) के हवाले से तफ़्सील दी गई है कि किस तरह मुसलमान पीछे रह गए और इसमें कांग्रेस की लंबी हुकूमत का क्या किरदार रहा:

1. तालीमी पसमंदगी (शैक्षणिक पिछड़ापन)

रिपोर्ट ने साबित किया कि मुसलमान तालीम के मैदान में सबसे पिछली सफ़ (लाइन) में खड़े हैं।

- **लिटरेसी रेट:** मुसलमानों की ख़्वांदगी (साक्षरता दर) 59.1% थी, जो कि क़ौमी औसत (national average) 64.8% से काफ़ी कम थी।

- **हायर एजुकेशन:** ग्रेजुएशन (B.A, B.Sc) करने वालों में मुसलमान सिर्फ़ 3.4% थे, जबकि क़ौमी औसत 7% था।

- **स्कूल ड्रॉपआउट:** 6 से 14 साल की उम्र के 25% मुसलमान बच्चे या तो कभी स्कूल गए ही नहीं, या उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी।

- **नुक़सान का तज़्ज़िया:** कांग्रेस ने लगातार हुकूमत की, लेकिन मुसलमान बाहुल्य (Muslim-majority) इलाक़ों में सरकारी स्कूल और कॉलेज खोलने में शदीद लापरवाही बरती गई। मुसलमानों को मदरसों तक महदूद छोड़ दिया गया (हालांकि रिपोर्ट ने बताया कि सिर्फ़ 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, बाक़ी 96% सेक्युलर एजुकेशन चाहते थे पर उन्हें सहूलत नहीं मिली)।

2. सरकारी नौकरियों में नुमाइंदगी (Government Employment)

सरकारी नौकरियां किसी भी तबक़े की माशी मज़बूती का सुबूत होती हैं, लेकिन यहां मुसलमानों का हाल सबसे ख़राब था। हालांकि मुसलमानों की आबादी उस वक़्त देश में लगभग 13.4% थी:

- **IAS और IPS:** IAS में मुसलमान सिर्फ़ 3%, IFS में 1.8%, और IPS में सिर्फ़ 4% थे।

- **रेलवे और पोस्ट ऑफ़िस:** इंडियन रेलवे, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, उसमें मुसलमान सिर्फ़ 4.5% थे। डाक विभाग (Postal department) में यह आंकड़ा सिर्फ़ 5% था।

- **सिक्योरिटी एजेंसीज़ और पुलिस:** पुलिस फ़ोर्स में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ़ 4% थी। ख़ुफ़िया एजेंसीज़ (Intelligence) और फ़ौज में तो इनकी तादाद ना के बराबर थी।

- **नुक़सान का तज़्ज़िया:** आज़ादी के बाद से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का हिस्सा मुसलसल गिरता गया। कांग्रेस ने अक़लियतों (minorities) के हुक़ूक़ की बातें तो कीं, लेकिन भर्तियों (recruitments) में सही नुमाइंदगी (fair representation) दिलाने के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई।

3. माशी हालत और बैंक लोन (Economy and Credit)

मुसलमान ज़्यादातर छोटे कारोबार, दस्तकारी (artisans), और मैकेनिक के पेशों से जुड़े हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैपिटल (सरमाया) चाहिए था।

- **बैंक लोन:** सच्चर रिपोर्ट ने बताया कि मुसलमानों को बैंकों से मिलने वाला लोन सिर्फ़ 4.7% था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) में उनका हिस्सा बेहद कम था।

- **ग़रीबी (Poverty):** 31% मुसलमान ग़रीबी की रेखा (Poverty Line) से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे थे।

- **रेड-लाइनिंग:** रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कई बैंकों ने मुसलमान बाहुल्य इलाक़ों को “नेगेटिव ज़ोन” या “रेड ज़ोन” घोषित किया हुआ था, जहां वो लोन देना ही नहीं चाहते थे।

- **नुक़सान का तज़्ज़िया:** कांग्रेस के दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण (nationalization) हुआ, लेकिन मुसलमान इलाक़ों में बैंकों की शाखाएं (branches) नहीं खोली गईं। मुसलमान कारख़ानों के मज़दूर और छोटे दुकानदार बनके रह गए, और उन्हें मेनस्ट्रीम इकॉनमी से काट दिया गया।

4. बुनियादी सहूलियात (Infrastructure) का फ़ुक़दान

जिस इलाक़े में मुसलमान ज़्यादा थे, वहां सरकारी विकास (development) सबसे कम पहुंचा।

- रिपोर्ट के मुताबिक़, मुसलमान आबादी वाले गांवों और मोहल्लों में पक्की सड़कें, बस स्टॉप्स, और सरकारी अस्पताल (medical facilities) की शदीद कमी थी।

- सफ़ाई और पीने के पानी का निज़ाम इन इलाक़ों में बाक़ी आबादियों के मुक़ाबले में सबसे ख़राब था।

कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या नुक़सान पहुंचाया? (हक़ीक़त का आईना)

सच्चर कमेटी के इन आंकड़ों ने "मुस्लिम तुष्टिकरण" (Muslim Appeasement) के उस झूठ को बेनक़ाब कर दिया जो सालों से फैलाया जा रहा था। इन आंकड़ों की रौशनी में कांग्रेस का मुसलमानों को पहुंचाया गया नुक़सान दर्ज़-ज़ैल (निम्नलिखित) है:

- **वोट बैंक की सियासत (The Politics of Fear):** कांग्रेस ने मुसलमानों के दिलों में हमेशा "कम्युनल फ़ोर्सेज़" (फ़सादी ताक़तों) का डर बिठा कर उनका वोट लिया। जब आबादी को डर के साये में रखा जाता है, तो उनकी मांगें तालीम और रोज़गार से हट कर सिर्फ़ "जान और माल के तहफ़्फ़ुज़" (security) तक महदूद हो जाती हैं। कांग्रेस ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्हें डेवलपमेंट के हक़ से महरूम रखा।

- **सियासी नुमाइंदगी (Political Representation) का ख़ात्मा:** मुसलमानों को सिर्फ़ सिंबल (प्रतीक) बनाया गया। इफ़्तार पार्टियों और ईद मिलन जैसे दिखावे के प्रोग्राम किए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पर उन्हें आगे बढ़ने के बराबर मौक़े नहीं दिए गए।

- **पसमंदगी पर पर्दा:** 60 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों को यह एहसास दिलाया कि सरकार उनके साथ है, जबकि अंदर ख़ाने सिस्टम उन्हें हर फ़ील्ड में पीछे धकेल रहा था। अगर सच्चर रिपोर्ट ना आती, तो मुसलमानों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो दलित और आदिवासी तबक़ों से भी पीछे जा चुके हैं।

सच्चर रिपोर्ट के बाद के क़दम और ज़मीनी हक़ीक़त

सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद यूपीए सरकार पर काफ़ी दबाव (pressure) आया और उन्हें समझ आ गया कि अब सिर्फ़ बातों से काम नहीं चलेगा। 2006 के बाद से यूपीए और उसके बाद आने वाली एनडीए सरकार ने अपनी-अपनी पॉलिसी के मुताबिक़ क़दम उठाए।

सरकार ने सच्चर कमेटी की 76 सिफ़ारिशों (recommendations) में से 72 को मंज़ूर किया और इन पर अमल करने के लिए 43 अहम फ़ैसले किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़मीनी हालत में कोई सुधार आया? इसका जवाब "हां" और "नहीं" दोनों में है। आइए इसका तफ़्सीली तज़्ज़िया करते हैं:

1. यूपीए सरकार के क़दम (2006-2014)

सच्चर रिपोर्ट आने के बाद यूपीए सरकार ने अक़लियतों (minorities) के लिए कुछ मख़सूस (specific) स्कीम्स शुरू कीं:

- **स्कॉलरशिप स्कीम्स:** मुसलमान बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, और मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप्स शुरू की गईं। इसका मक़सद स्कूल ड्रॉपआउट रेट को कम करना था।

- **मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (MsDP):** ऐसे 90 से ज़्यादा ज़िलों (districts) की पहचान की गई जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और विकास कम था। यहां अस्पताल, स्कूल, और सड़कें बनाने के लिए अलग से बजट दिया गया।

- **प्रधानमंत्री 15-पॉइंट प्रोग्राम:** सरकारी स्कीम्स (जैसे ICDS, सर्व शिक्षा अभियान) का 15% हिस्सा अक़लियतों वाले इलाक़ों और उनके फ़लाह के लिए तय किया गया।

- **बैंक लोन (Priority Sector Lending):** बैंकों को हिदायत दी गई कि वो अपने टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लोन का 15% हिस्सा अक़लियतों को दें ताकि वो छोटा कारोबार शुरू कर सकें।

2. <u>एनडीए सरकार के क़दम (2014-वर्तमान)</u>

2014 में जब बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए सरकार आई, तो उनकी अप्रोच "माइनॉरिटी-स्पेसिफिक" से हट कर "सबका साथ, सबका विकास" (General Welfare) पर शिफ़्ट हो गई।

- **जनरल स्कीम्स पर ज़ोर:** एनडीए सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (मकान), मुद्रा योजना (लोन), और उज्ज्वला योजना (गैस सिलेंडर) जैसी आम अवामी स्कीम्स का मुसलमानों को बराबर फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए सिर्फ़ उनके लिए अलग स्कीम्स ज़रूरी नहीं हैं।

- **PMJVK का नया रूप:** यूपीए के 'MsDP' प्रोग्राम का नाम बदल कर 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) कर दिया गया और इसका दायरा और बड़ा कर दिया गया।

- **स्किल डेवलपमेंट:** 'सीखो और कमाओ', 'नई मंज़िल', और 'हुनर हाट' जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए गए ताकि मुसलमान दस्तकारों (artisans) और नौजवानों को रोज़गार मिल सके।

- **स्कीम्स में कटौती (Cuts):** हाल ही में सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप (MANF) को बंद कर दिया और क्लासेस 1 से 8 तक की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी यह कह कर महदूद कर दिया कि राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत 8वीं क्लास तक तालीम वैसे भी मुफ़्त है।

3. ज़मीनी हक़ीक़त: क्या हालात बेहतर हुए?

इस बात का पता लगाने के लिए ख़ुद यूपीए सरकार ने 2013-14 में प्रोफ़ेसर अमिताभ कुंडू की क़यादत में एक "पोस्ट-सच्चर इवैल्यूएशन कमेटी" बनाई थी, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। कुंडू रिपोर्ट और हाल ही के दीगर आंकड़ों से ज़मीनी हक़ीक़त कुछ ऐसी सामने आई:

- **A. तालीम (Education) में मामूली सुधार:** स्कॉलरशिप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि स्कूल ड्रॉपआउट रेट कम हुआ और मुस्लिम बच्चों (ख़ास तौर पर लड़कियों) के स्कूल जाने की तादाद बढ़ी। लेकिन हायर एजुकेशन (Graduation/Post Graduation) में मुसलमान अभी भी नेशनल एवरेज से काफ़ी पीछे हैं।
    - **इम्प्लीमेंटेशन फ़ेल्योर:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) स्कीम के तहत मुस्लिम आबादी वाले ज़िलों में 824 स्कूल्स मंज़ूर हुए थे, लेकिन 2020 तक इनमें मुस्लिम लड़कियों का एनरोलमेंट सिर्फ़ 13.71% तक ही हो पाया था।
- **B. फंड का इस्तेमाल ना होना (Under-utilization):** कई बार बजट तो अलॉट होता है, लेकिन सरकारी सुस्ती और अफ़सरशाही (bureaucracy) की वजह से ख़र्च ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर, 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान में अक़लियतों के लिए लगभग ₹14,328 करोड़ रखे गए थे, लेकिन सिर्फ़ ₹7,005 करोड़ ही ख़र्च किए गए।
- **C. सरकारी नौकरियों और मइशत (Economy) में नाकामी:** सच्चर कमेटी का सबसे बड़ा चिंता का विषय सरकारी नौकरियां थीं। अफ़सोस की बात यह है कि आज भी पुलिस,

IAS/IPS, या रेलवे में मुसलमानों की नुमाइंदगी (representation) में कोई ख़ास इज़ाफ़ा (increase) नहीं हुआ है। कुंडू रिपोर्ट ने भी बताया कि फ़ॉर्मल सेक्टर (पक्की नौकरियों) में अभी भी मुसलमानों की पहुंच बहुत कम है और वो अभी भी डेली वेज या छोटे कारोबार (informal sector) पर निर्भर हैं।

- **D. सियासी नुमाइंदगी (Political Representation):** एक कड़वा सच यह भी है कि गुज़िश्ता एक दहाई (decade) में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ में मुसलमान सांसदों और विधायकों की तादाद में कमी आई है, जिसकी वजह से पॉलिसी-मेकिंग में उनकी आवाज़ और कमज़ोर हुई है।

ख़ुलासा (निष्कर्ष)

कांग्रेस की सेक्युलर आइडियोलॉजी ने भारत के मुसलमानों को आईनी बराबरी ज़रूर दी, लेकिन उनकी लंबी हुकूमत में मुसलमानों की ज़मीनी तरक़्क़ी को शदीद नुक़सान पहुंचा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट इस बात का सुबूत है कि "मुस्लिम तुष्टिकरण" (appeasement) का दावा खोखला था; हक़ीक़त में लगातार नज़रंदाज़ी (neglect) और वोट-बैंक की सियासत ने मुसलमानों को तालीमी, माशी और समाजी तौर पर पीछे धकेल दिया।